circulated a Model Bill to all the States/ Union Territories to enable them to enact suitable legislation for regulation and control of ground water development. So far only the States of Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu and Madhya Pradesh have enacted legislations for this purpose.

(c) Water being a State subject, suitable legislation on the line of the Model Bill has to be enacted by the State Governments.

(d) and (e) Does not arise.

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत गुजरात के कच्छ और बनासकांठा जिलों को प्रदान की जाने वाली निधियां

859. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुकला:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत गुजरात के कच्छ तथा बनासकांठा जिलों को विगत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) क्या पंचायत राज प्रणाली के अंतर्गत उक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग किया गया;

(ग) इस योजना के अंतर्गत इन जिलों के कुल कितने बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया और चालू वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है; और

(घ) तत्संबंधी जिले-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजरापू येरन्नायडु): (क) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत गुजरात के कच्छ और बनासकांठा जिलों को गत तीन वर्षों के दौरान आंवटित राशि का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(रुपए लाख में)

जिला	1994-95	1995-96*	1996-97
कच्छ	583.40	312.20	177.19
बनासकांठा	831.62	532.78	278.91

*(इन्दिरा आवास योजना और दस लाख कुओं की योजना सहित)

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत वास्तविक प्रगति को सृजित श्रमदिनों की संख्या के अनुसार मापा जाता है। इन जिलों में गत तीन वर्षों के दौरान सृजित श्रमदिन और चालू वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य नीचे दिए जाते हैं:

(संख्या लाख में)

जिला	वर्ष	सृजित श्रमदिन
कच्छ	1994-95	11.36
	1995-96	7.40
	1996-97	3.90
	1997-98	1.92 (लक्ष्य निर्धारित)
बनासकांठा	1994-95	15.81
	1995-96	9.66
	1996-97	4.80
	1997-98	3.02 (लक्ष्य निर्धारित)

Employment of the Rural Youths in Assam, Madhya Pradesh and Rajasthan

860. SHRI PARAG CHALIHA:

SHRI GOVINDRAM MIRI:

Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) what are the details of the schemes/plans/proposals of the Ministry to provide emloyment to the Youth in Assam, Madhya Pradesh and Rajasthan, that have been introduced during Eighth Five Year Plan period; and

(b) what has been the achievement level in each case as on date?

THE MINISTER OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI K. YERRANNAIDU): (a) Jawahar Rozgar Yojana (JRY), Employment Assurance Scheme (EAS), and Integrated Rural Development Programme (IRDP) are major employment programmes that have been implemented by the centre throughout the country includino the

States of Assam, Madhya Pradesh and Rajasthan during the Eighth Five Year Plan.

(b) Physical achievements in respect of the above programmes for Assam, Madhya Pradesh and Rajasthan during the Eighth Five Year Plan are given below:—

	Assam	Madhya Pradesh	Rajasthan
JRY	921.87	3742.63	1864.88
EAS*	471.45	1182.28	823.78
IRDP	263296	1016200	488854

*EAS started from 1993-94.

Note: Achievements are in lakh mandays generated for JRY & EAS and no. of families benefited for IRDP.

आठवीं योजनावधि के दौरान गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य और प्राप्त की गई उपलब्धियां

861. **श्री नागमणि:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के अन्त तक एक हजार तक की जनसंख्या वाले गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) क्या यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) इस संबंध में निधारित किए गए लक्ष्यों और प्राप्त की गई उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) जिन राज्यों में लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके हैं उनके कारणों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्र (श्री किंजराप येरन्नायडु): (क) से (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना वाले गांवों को सड़क, मार्ग से जोड़ने के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

Unspent Balance of the Centrally Allocated Amount for the States

862. SHRI NILOTPAL BASU: Will the Miniter of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the time schedule and the corresponding amount of Central Allocation reaching the States in absolute number of percentage-wise for each State, Scheme-wise, during the last three years;

(b) whether it is a fact that substantial part of the money is reaching the States in the last week of March, is leading to huge unspent balance and if so, the details thereof; and

(c) whether the unspent balance is immediately returned to the GOI or retained in the State and the details thereof, State-wise.?

THE MINISTER OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI K. YERRANNAIDU): (a) to (c) The amount of central allocations under major poverty alleviation and Rural Development Schemes *viz. (i)* Integrated Rural Development Programme (IRDP), (ii) Jawahar Rozgar Yojana (JRY), (III) Employment Assurance Scheme (EAS) and (iv) Accelerated Rural Water Supply Programme are released in two instalments to the State Govts./UTs. While the first instalment equivalent to 50% of Central allocation is released to DRDAs/States in the beginning of the financial year, second instalment amounting to remaining 50% is released on receipt of Audit Reports and utilisation certificates of the previous year. The release of the second instalment sometime gets delayed due to non-receipt of requisite documents from the DRDAs/State Govts. The details of